दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 05 जुलाई 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-273

वर्ष 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की जरुरतः सीतारमण

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2018-19 की आर्थिक समीक्षा पेश की। देश के उद्योग और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के विश्लेषण में समीक्षा में कहा गया है कि भारत को एक मजबूत और लचीले बुनियादी ढांचे के साथ औद्योगिक व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें लचीलापन हो। वर्ष 2018-19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में औद्योगिक विकास की दर वर्ष 2017-18 की 4.4 प्रतिशत की तुलना में 3.6 प्रतिशत रही। वर्ष 2018-19 के दौरान यह गिरावट मुख्य तौर पर मध्यम एवं लघु उद्योगों को धीमे क्रेडिट प्रवाह आदि की वजह से तीसरी और चौथी तिमाही में धीमी विनिर्माण गतिविधियों के कारा रही। इस बीच, आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा सहायक उद्योगों ने वर्ष 2018-19 के दौरान 4.3 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर हासिल की, जो वर्ष 2017-18 में प्राप्त वृद्धि दर के बराबर है।

समीक्षा में कहा गया है कि सरकार ने विनिर्माण वृद्धि को तेज गति देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों जैसे स्टार्ट-अप इंडिया, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति सुधार आदि में अनेक उपायों की शुरूआत हुई है। वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में 190 देशों की रैंकिंग में भारत ने 77वां स्थान हासिल किया है। सरकार एक उदार एफडीआई नीति के जरिए निवेश को बढ़ावा देने में अग्र-सक्रिय भूमिका निभा रही है। वर्ष 2018-19 के दौरान एफडीआई इचि टी में कुल अंतर्वाह 44.36 अरब डॉलर था, जबकि 2017-18 के दौरान यह 44.85 अरब अमरीकी डॉलर था। सौभाग्य, पीएमएवाई आदि जैसे क्षेत्र विशेष प्रमुख कार्यक्रमों के लागू होने से सतत और लचीले बुनियादी ढांचे को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में सड़कों का निर्माण प्रति दिन 30 किलोमीटर की दर से बढ़ा, जबकि 2014-15 में यह 12 किलोमीटर प्रति दिन था। रेल भाड़ा और यात्रियों की आवाजाही 2017-18 के 0.64 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 5.33 प्रतिशत बढ़ गया। भारत में 2018-19 में कुल टेलीफोन कनेक्शन 118.34 करोड़ तक पहुंच गए। बिजली की स्थापित क्षमता 2018 में 3,44,002 मेगावाट से बढ़कर 2019 में 3,56,100 मेगावाट हो गई।

समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2018-19 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन में वर्ष 2017-18 की तुलना में सुधार हुआ है। वास्तविक सकल मूल्यवर्धित (जीवीए) औद्योगिक विकास की दर वर्ष 2017-18 में 5.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गई। आईआईपी के अनुसार औद्योगिक विकास दर 2017-18 में 4.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 में 3.6 प्रतिशत थी। वर्ष 2018-19 के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में क्रमशः 2.9 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्य कर रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 257 उद्यमों में से 174 उद्यम लाभ की स्थिति में थे और दो लाभ नहीं और हानि नहीं की स्थिति में थे। समीक्षा में कहा गया है कि सीपीएसई के प्रदर्शन में सुधार की काफी गुंजाइश है।

समीक्षा में आगे कहा गया है कि उद्योग में सकल पूंजी निर्माण की वृद्धि दर 2016-17 में (-) 0.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 7.6 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो उद्योग में निवेश की बढ़ोतरी को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में सकल बैंक क्रेडिट प्रवाह में मार्च 2018 में 0.7 प्रतिशत हुई वृद्धि की तुलना में मार्च 2019 में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

महत्वपूर्ण एवं खास

विमान का इंजन फेल होने से हुई आपातकालीन लैंडिंग

मुंबई (आरएनएस)। ओमान एयर की मुंबई-मस्कट उड़ान की टेक आफ के तुरंत बाद इंजन फेल होने की वजह से बुधवार शाम को मुंबई हवाईअड्डे पर सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। इस उड़ान में 200 से ज्यादा लोग सवार थे। फ्लाइट डब्ल्यूवाई204 ने शाम करीब 4.15 बजे उड़ान भरी थी। इसकी महज 10 मिनट में आपात लैंडिंग करानी पड़ी। ऐसा विमान के एक इंजन के फेल होने की वजह से किया गया। इसके मद्देनजर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित किया गया था। विमान को शाम करीब 4.50 बजे एक इंजन के साथ सुरक्षित लैंड करा लिया गया। इस विमान में करीब 205 यात्री सवार थे और इस घटना के दौरान किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

नियंत्रण रेखा के पास भीषण विस्फोट, 5 पाक सैनिकों की मौत

इस्लामाबाद। नियंत्रण रेखा के पास बुधवार को हुए विस्फोट में पाकिस्तानी सेना के पांच जवान मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। स्थानीय मीडिया ने पाकिस्तान सशस्त्र बलों की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के बयान के हवाले से कहा कि चांब सेक्टर में हुई इस घटना की जांच की जा रही है। घटना के लिए भारतीय सेना पर युद्ध विराम का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। मारे गए सैनिकों के नाम बताने के साथ ही कहा गया कि घटना का कारण द्विपक्षीय युद्ध विराम के साथ-साथ यह अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी भी है।इसमें दावा किया गया कि यह घटना राज्य प्रायोजित आतंकवाद का सबूत है। आईएसपीआर ने मृतकों की पहचान सूबेदार मोहम्मद सादिक, सिपाही मोहम्मद तैय्यब, नायक शेर जमन, सिपाही जोहेब व सिपाही गुलाम कासिम के रूप में की है।

होंडुरास के तटीय क्षेत्र में खराब मौसम के कारण जहाज डूबा, 27 की मौत, नौ लापता

मेक्सिको सिटी। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास के तटीय क्षेत्र में कैरेबियाई सागर में खराब मौसम के कारण मछली पकड़ने वाला एक जहाज समुद्र में डूब गया जिससे कम से कम 27 मछुआरों की मौत हो गई। सेना के जानकारी देते हुए कहा कि घटना के बाद 55 लोगों को बचाया गया है जबकि नौ अभी भी लापता हैं। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि दुर्घटना तट से लगभग 40 समुद्री मील दूर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा संभवतः समुद्री क्षेत्र में तेज हवाओं के चलने अथवा ऊंची लहरों के कारण हुआ। कैरेबियाई व्यावसायिक मछुआरा एसोसिएशन का कहना है कि घटना के बाद आसपास की नौकाओं और जहाजों को मदद के लिए बुलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि उसी क्षेत्र में मछली पकड़ने वाला एक अन्य जहाज भी डूबा था लेकिन उसपर सवार सभी 49 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है।

भारतीय युवाओं का प्रतिनिधिमंडल चीन दौरे पर

» भारतीय दूतावास में स्वागत समारोह

बीजिंग। इस साल युवा एक्सचेंज 2019 समारोह के तहत भारत सरकार के खेल मंत्रालय की ओर से 200 भारतीय युवाओं का प्रतिनिधिमंडल चीन के दौरे पर आया है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार किरण सोनी गुप्ता (आईएएस अधिकारी) कर रही हैं। पेइचिंग में बुधवार को भारतीय दूतावास ने दौरे पर आए इस प्रतिनिधिमंडल के लिए एक स्वागत समारोह की मेजबानी की। इस अवसर पर भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने युवाओं को संबोधित किया और कहा कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भारत और चीन के युवाओं के लिए एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का एक अवसर है। उन्होंने युवाओं को भारत-चीन संबंध के मैत्रीपूर्ण विकास में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं, केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार किरण सोनी गुप्ता ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच गहरा ऐतिहासिक संबंध है।

मुश्किल वक्त में पीठ दिखाना सैनिक की 'कायरता'

» सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फरमान

नईदिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक सैनिक को देश की अखंडता की रक्षा के प्रत्येक अवसर पर आगे बढ़ना चाहिए और यदि वह गंभीर स्थिति में चुनौती से मुंह मोड़ता है तो निश्चित ही यह कायरता होगी. सुप्रीम कोर्ट ने एक सैनिक की सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका अस्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की. इस सैनिक को 2006 में जम्मू कश्मीर में एक अभियान के दौरान उसकी चौकी पर जब आतंवादियों ने गोलियां बरसायीं तो जवाबी कार्रवाई करने के बजाए चौकी से भाग जाने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. इस हमले में सैनिक का एक साथी मारा गया था. इस सैनिक पर अपनी एके-47 राइफल और पिस्तौल का इस्तेमाल करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था क्योंकि इस वजह से उग्रवादियों ने घेराबंदी तोड़ दी थी. जबकि एक सैनिक की जान लेने के साथ ही हल्की मशीनगन लेकर फरार हो गये थे. जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि एक जवान को जवाबी कार्रवाई करने और राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करने के लिए हमलावरों के साथ संघर्ष करने के मकसद से प्रशिक्षित करने पर देश के संसाधन खर्च किए जाते हैं.

प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी 5000 डॉलर बढ़ाने ऊर्जा खपत ढ़ाई गुणा बढ़े

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2018-19 की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत का एक तिहाई है, जिसे ढ़ाई गुना बढ़ाकर उच्च मध्यम आय समूह में प्रवेश करने के लिए 2010 के मूल्यों में प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी 5000 डॉलर करने की आवश्यकता है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत को 0.8 के एचडीआई स्तर तक पहुंचाने के लिए अपनी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत चार गुना बढ़ानी होगी। इसके लिए बड़े स्तर पर संसाधन की आवश्यकता होगी, जिसे समय के अनुसार बढ़ाना होगा।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत की आबादी विश्व जनसंख्या का लगभग 18 प्रतिशत है, लेकिन भारत विश्व के प्राथमिक ऊर्जा का लगभग 6 प्रतिशत उपयोग करता है। वैश्विक प्रति व्यक्ति 1.8 तेल समतुल्य औसत की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 0.6 टन तेल समतुल्य के बराबर है।

ऊर्जा खपत तथा विभिन्न सामाजिक संकेतकों के बीच घनिष्ट संपर्क की चर्चा करते हुए आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया का स्तम्भ है। सरकार की प्राथमिकता सतत् तथा स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करना है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत का आर्थिक भविष्य और समृद्धि उसके द्वारा अपने सभी नागरिकों को किफायती, विश्वसनीय तथा सतत् ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करती है।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि ऊर्जा सक्षमता एक रणनीति है, जो ऊर्जा संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से सुखद स्थिति ला सकती है। समीक्षा में कहा गया है कि भविष्य के नीतिगत निर्देश में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा सक्षमता कार्यक्रमों को बढ़ाने के साथ-साथ अधिक समृद्धि के लिए देश के प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के तकनीकी समाधान शामिल किए जाने चाहिए।

राहुल को 15 हजार के मुचलके पर मिली अग्रिम जमानत

» मानहानि केस

मुंबई (आरएनएस)। आरएसएस के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर किए गए मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आग्रिम जमानत मिल गई है। आरोप था कि राहुल गांधी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी-आरएसएस की विचारधारा से जोड़ा था। कोर्ट के बाहर कांग्रेस समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और मिलिंद देवड़ा भी मौजूद हैं।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल ने अपने आपको बेकसूर बताया। इसके बाद कोर्ट ने 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दिया। पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जमानत ली। ज्ञात हो कि गौरी लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरु में उनके घर के गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस दौरान, राहुल की अगुआई में पार्टी नेता कृपाशंकर सिंह, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, संजय निरूपम अदालत के अंदर मौजूद हैं। इससे पहले जब राहुल गांधी कोर्ट में पेशी के लिए मुंबई पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे लगाए। कांग्रेस समर्थकों ने राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए।

शिकायतकर्ता ध्रुतिमन जोशी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी पर भी ऐसे मामले दायर किए थे जिन्हें खारिज कर दिया गया था। जोशी ने अपनी याचिका में कहा कि लंकेश की हत्या के मुश्किल से 24 घंटों के बाद ही राहुल गांधी ने हत्या के लिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को जिम्मेदार ठहरा दिया था।

महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ किसी आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई यह दूसरी याचिका है। इससे पहले 2014 में, एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कथित रूप से आरएसएस पर आरोप लगाने के लिए राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी। वह मामला ठाणे में भिवंडी अदालत में लंबित है।

अब दुबई के एयरपोर्टों पर रुपये में किया जा सकेगा लेनदेन

दुबई। संयुक्त अरब अमीरात के एक नामचीन अखबार के मुताबिक दुबई के सभी एयरपोर्टों पर भारतीय रुपये में लेनदेन किया जा सकेगा। भारतीय मुद्रा को लेनदेन के लिए स्वीकार किया जाना भारत से आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि उन्हें रुपये को दूसरी मुद्राओं में परिवर्तित कराने के चलते बड़ी राशि गंवानी पड़ती थी। गल्फ न्यूज समाचार पत्र की एक खबर के अनुसार, भारतीय मुद्रा दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सभी तीनों टर्मिनल और अल मख्तूम हवाई अड्डे पर स्वीकार्य है। हवाई अड्डे पर स्थित ड्यूटी फ्री दुकान के एक कर्मचारी ने समाचार पत्र को बताया, हां, हमने भारतीय रुपया लेना शुरू कर दिया है। खबर में कहा गया है कि पिछले साल दुबई हवाई अड्डे से लगभग 9 करोड़ यात्री गुजरे थे, इनमें 1.22 करोड़ भारतीय थे। भारतीय यात्रियों को इससे पहले तक दुबई हवाई अड्डे पर ड्यूटी फ्री दुकानों से खरीददारी के लिए सामान की कीमत डॉलर, दिरहम या यूरो में चुकानी पड़ती थी।

धान की एमएसपी 85 रु. प्रति क्विंटल बढ़ी, वेज कोड बिल को मंजूरी

» मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को बंपर तोहफा दे दिया है। मोदी कैबिनेट की बैठक आज धान की एमएसपी 85 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी है। अब धान की एमएसपी बढ़कर 1835 रु प्रति क्विंटल हो गई।

धान के अलावा मक्का, बाजरा, मूंगफली, तुर समेत 13 और अनाजों की एमएसपी बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है। मोदी सरकार ने वेज कोड बिल को भी पास करने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार ने इस साल देशभर में 357 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले सीजन 2018-19 में सरकारी खरीद एजेंसियों ने देशभर में 357.95 लाख टन गेहूं की खरीदी थी।

एफसीआई आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में सबसे ज्यादा 127.01 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए तय लक्ष्य 125 लाख टन से अधिक है।

केजरीवाल 12 जुलाई को शुरु करेंगे मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की तीर्थ यात्रा योजना का आगाज़ 12 जुलाई को करेंगे और योजना के तहत दिल्ली-अमृतसर-बाघा बॉर्डर-आनंदपुर साहिब टूर सर्किट के लिए 1000 तीर्थ यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन को रवाना करेंगे। यह जानकारी दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने दी। इस योजना के तहत पूरी यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। गहलोत ने कहा कि योजना के तहत अब तक पांच गलियारों का चयन किया गया है जिसमें दिल्ली-मथुरा-वृदांवन-आगरा-फतेहपुर सीकरी, दिल्ली-हरिद्वार-ऋषिकेश-नीलकंठ, दिल्ली-अजमेर-पुष्कर, दिल्ली-अमृतसर-बाघा बॉर्डर-आनंदपुर साहिब और दिल्ली-वैष्णों देवी-जम्मू शामिल हैं।

भारतीय रेलवे में अब रेल दुर्घटनाएं शून्य हो गईः सीतारमण

» रेलवे के माल दुलाई से राजस्व में 5.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

» 10 रेलवे स्टेशनों, 34 वर्कशापों और 4 उत्पादक ईकाइयों को ग्रीन इंडस्ट्रिज सर्टिफिकेट मिला

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की। उन्होंने समीक्षा के दौरान बताया कि हादसों से संबंधित रेलवे के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 के दौरान ट्रेनों के टकराने के मामले शून्य हो गए और रेलगाड़ियों के बेपटरी होने की घटना 2016-17 के 78 से घटकर 2018-19 में 46 हो गई।

आर्थिक समीक्षा के मुताबिक 2018-19 के दौरान रेलवे ने 1159.55 मिलियन टन की माल ढुलाई (कोंकण रेलवे द्वारा किए गए लदान को छोड़कर) से राजस्व हासिल किए जबकि 2016-17 की अवधि में यह आंकड़ा 1106.15 मिलियन टन दर्ज किया गया था। यानी 2016-17 के मुकाबले 2018-19 में 53.49 मिलियन टन, 4.83 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारतीय रेलवे ने 1221.39 मिलियन टन का राजस्व अर्जक माल भाड़ा लदान किया था जो वर्ष 217-18 के माल भाड़ा यातायात से 61.84 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है, अर्थात इसमें 5.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 2.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में भारतीय रेलवे में यात्रा करने वालों की संख्या में 0.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण करने के लए एक प्रमुख कार्यक्रम की शुरुआत की है। इससे आयातित डीजल तेल पर देश की निर्भरता कम होगी। 01 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे के पास विद्युत चालित 35,488 किलोमीटर मार्ग का नेटवर्क है, जो कुल नेटवर्क का 51.85 प्रतिशत है और 64.50 प्रतिशत माल ढुलाई करता है जबकि 53.70 प्रतिशत कोचिंग ट्रैफिक का वहन करता है। विद्युतीकरण की गति में वृद्धि हुई है और वर्ष 2021 तक इसे बढ़ाकर 38000 किलोमीटर करना तय किया गया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि स्वच्छ रेलवे, स्वच्छ भारत, मिशन स्वच्छता पर केंद्रित है।

सरकार की प्राथमिकता है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल सुनिश्चित करना

नईदिल्ली (आरएनएस)। सरकार की प्राथमिकता निरंतर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को सुनिश्ति करने की है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक समीक्षा 2018-19 संसद में पेश की। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के जरिये बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत 7 करोड़ घर एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुख्य काम घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी के निरंतर इस्तेमाल से स्वच्छ ऊर्जा को सुनिश्चित करना है। इसके लिए एलपीजी के रिफिलिंग को निरंतर जारी रखने की बात कही गई है। आर्थिक समीक्षा में यह भी कहा गया है कि 21.44 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचने के साथ ही भारत ने करीब 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

आर्थिक समीक्षा के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भोजन पकाने के लिए एलपीजी की स्वीकार्यता है। भोजन पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ा है, रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि शहरों में भोजन बनाने के लिए एलपीजी ईंधन का एक प्राथमिक स्रोत है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि सब्सिडी लिकेज को रोकने के लिए एलपीजी उपभोक्ता के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटीएल) जिसे 'पहल' के नाम से भी जाना जाता है, 15 नवंबर 2014 को देश के 54 जिलों में लॉन्च की गई थी। 5 मार्च 2019 के मुताबिक 24.39 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता अब इस योजना से जुड़ चुके हैं।